

प्रेमक,

एन0एस0नपलध्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

रीवा में

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून, दिनांक 10 अक्टूबर, 2007

विषय:- गै0 कोटेक हेल्थ कोयर प्रा0लि0 को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु जनपद हरिद्वार की ताहसील रुड़की के ग्राम किशनपुर जमालपुर मुस्ताहकम में कुल 0.1738 हे0 अतिरिक्त भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-987/भूमि व्यवस्था-भू0क0 दिनांक 23 अगस्त, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि गै0 कोटेक हेल्थ कोयर प्रा0लि0 को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विभाज एव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुवृत्तन एव उपांतरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(V) के अन्तर्गत ताहसील रुड़की के ग्राम किशनपुर जमालपुर मुस्ताहकम में श्री इशमसिंह, शिवचन्द भुजगण फूलसिंह व श्रीमती फुल्ली विधवा फूल सिंह निवासी ग्राम किशनपुर जमालपुर मुस्ताहकम की गाटा सं0 596/1म, रकबाई 0.0125 हे0 व 598म0 रकबाई 0.5087 हे0 कुल रकबा 0.5212 हे0 में से अपना कुल 1/3 भाग अर्थात् कुल 0.1738 हे0 अतिरिक्त भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- कैंटा धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर गतिविधि में कैंबल राज्य सरकार या जिले के फ्लैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- कैंटा धैक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधारी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लागों को भी ग्रहण कर सकेगा।

- 3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि यह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।
- 4- जिस भूमि का सक्कण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुरूचित जनजाति के न हों और अनुरूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का सक्कण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अराक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हो।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 7- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीआर)-2005 के अन्तर्गत GIDCR-2005 में उल्लिखित शर्तों के अधीन तथा इकाई का निर्माण कार्य सीआर से लेआउट स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 8- कय की जाने वाली भूमि का नू-उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही प्रस्तावित स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- प्रस्तावित उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10- प्रस्तावित इकाई द्वारा कय की जाने वाली अतिरिक्त भूमि का उपयोग मात्र Betta-lectum highly hygienic pharma product की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। इकाई को स्वयं के संशोधनों से आवश्यकता सुविधाओं का विकास करना होगा।

11- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में स्पष्ट जोनिंग क्षेत्र के लिये निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

12- इकाई में पूंजी निवेश से पूर्व ड्रग कण्ट्रोलर से ड्रग लाइसेन्स, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अग्निशमन आदि विभागों से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

13- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि कय की व्यवस्था के शर्तों में दी जा रही है। केन्द्रीय औद्योगिक पैकेंज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती है, जो इकाई की स्थापना के पश्चात् आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

14- उक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस०नपल व्याल)

प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2- आवुक्ता गढवाल मण्डल पोडी।
- 3- राधिका, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शारान।
- 4- श्री राजेन्द्र कुमार शिवारी, निदेशक, कोटक हेल्थ केयर प्रा० लि० ई-10 राउथ
साइड, जीटी रोड इन्डस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद।
- 5- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, राधियालय।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा री,

(गजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।